मांग संख्या 29

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन संचालित होने वाले 23 सिविल जिला तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मध्यस्थता केन्द्र के संचालन के लिए प्रति केन्द्र में 05 पदों के मान से कुल 120 पदों के सृजन हेतु ₹ 635.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

No.	Name of Post	Pay Scale/ Pay Matrix	No. of Post
1.	Co-ordinator [In the Rank of Addl. District & Sessions Judge (Entry Level)]	13 (A)	24
2.	Assistant Grade-III	Level-4	24
3.	Data Entry Operator-cum Typist	Level-4	24
4.	Peon	Level-1	48
Total			**120**

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 6,35,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 2

माननीय उच्च न्यायालय के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 372.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 3,72,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 3

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 4

न्यायाधीश वर्ग-1 एवं वर्ग-2 न्यायालय की स्थापना करने हेतु न्यायधीश वर्ग-1 के 20 पद तथा न्यायधीश वर्ग-2 के 30 पद, कुल 50 पदों के सृजन हेतु ₹ 900.00 लाख का व्यय संभावित है । विवरण निम्नानुसार है:-

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 (वेतनमान 78800-209200)

क्रमांक	जिला	स्थान	पद संख्या
1.	बलरामपुर	राजपुर	01
2.	बिलासपुर	बिलासपुर	02
		तखतपुर	01
3.	दुर्ग	दुर्ग	04
4.	जांजगीर-चांपा	पामगढ़	01
5.	कोरबा	पाली	01
6.	मुंगेली	लोरमी	01
7.	रायगढ़	रायगढ़	01
		सारंगगढ़	01
		घरघोड़ा	01
8.	रायपुर	रायपुर	05
		राजिम	01
योग			**20**
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (वेतनमान 56100-177500)			
1.	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	01
2.	बिलासपुर	बिलासपुर	01

3.	दुर्ग	दुर्ग	02
4.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	01
5.	कोरबा	कोरबा	01
6.	रायगढ़	रायगढ़	01
7.	रायपुर	रायपुर	01
8.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	01
9.	सुरजपुर	सुरजपुर	01
योग			**10**
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (वेतनमान 56100-177500)			
1.	बलौदाबाजार	भाटापारा	01
2.	बिलासपुर	बिलासपुर	02
		बिल्हा	01
3.	धमतरी	कुरूद	01
4.	दुर्ग	दुर्ग	02
5.	जंजगीर-चांपा	अकलतरा	01
6.	जशपुर	कुनकुरी	01
7.	कोरबा	कोरबा	01
		कटघोरा	01
8.	महासमुंद	महासमुंद	01
		बसना	01
9.	रायगढ़	सारंगढ़	01
		घरघोड़ा	01
10.	रायपुर	रायपुर	03
11.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	02
योग			**20**
कुल योग			**50**

नवनिर्मित राजस्व जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना के लिए पदों के सृजन हेतु ₹ 39.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	**पदनाम**	**वेतन मैट्रिक्स**	**पद संख्या**
1.	सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	लेवल-12	01
2.	स्टेनोग्राफर	लेवल-7	01
3.	प्रस्तुतकार	लेवल-7	01
4.	निष्पादन लिपिक	लेवल-4	01
5.	आदेशिका लेखक	लेवल-4	01
6.	साक्ष्य लेखक	लेवल-4	01
7.	आदेशिका वाहक	लेवल-1	01
8.	दफ्तरी कम फर्राश	लेवल-1	01
9.	भृत्य	लेवल-1	02
10.	चौकीदार	आकस्मिकता स्थापना	01
11.	वाटरमेन		01
12.	स्वीपर		01
कुल पद			**13**

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 9,39,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 5

सी.बी.आई. न्यायालय के लिए फर्नीचर, एयर कंडीशनर, वॉटर कूलर तथा फोटोकॉपियर के क्रय हेतु ₹ 3.33 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 3,33,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 6

कॉमर्शियल कोर्ट के लिए फर्नीचर, एयर कंडीशनर, वॉटर कूलर तथा फोटोकॉपियर के क्रय हेतु ₹ 3.33 लाख का व्यय संभावित है ।

कॉमर्शियल कोर्ट के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 5.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 8,83,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 7

परिवार न्यायालयों के स्थापनाओं सहित न्यायालयों, चेम्बर्स तथा बंगला ऑफिस में 2 टन क्षमता के 44 नग एसी क्रय हेतु ₹ 40.00 लाख एवं 1.5 टन क्षमता के 22 नग एसी के क्रय हेतु ₹ 29.26 लाख का व्यय संभावित है ।

परिवार न्यायालयों के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,19,26,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 8

परिवार न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने के लिए ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 9

जिला अधिवक्ता संघ कबीरधाम (कवर्धा) को ग्रंथालय के लिए अनुदान दिए जाने हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 5,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 10

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को आबंटित भूमि का नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के वार्षिक भू-भाटक प्रीमियम के भुगतान हेतु ₹ 286.86 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,86,86,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 11

छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संचालित कुल 33 मध्यस्थता केन्द्र के बुनियादी आवश्यकता (अधोसंरचना) के पूर्ति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, राजनांदगांव के लिए नव निर्मित ए.डी.आर. सेंटर के प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ₹ 231.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,31,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक 12

उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रजिस्ट्रार (ज्यूडिसियल) एवं रजिस्ट्रार (एस एण्ड ए) के लिए 02 नग वाहन (प्रति वाहन रू. 7.00 लाख) हेतु ₹ 14.00 लाख का व्यय संभावित है ।

उच्च न्यायालय, बिलासपुर में एडिशनल रजिस्ट्रार के लिए 03 नग वाहन (प्रति वाहन रू. 6.00 लाख) हेतु ₹ 18.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 32,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 13

प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बालोद के लिए 01 नग वाहन क्रय हेतु ₹ 6.500 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 6,50,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 14

02 परिवार न्यायालयों के लिए 02 नग वाहन (प्रति वाहन रू 7.00 लाख) क्रय हेतु ₹ 14.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 14,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

विशेष न्यायालयों के लिए फर्नीचर, एयर कंडीशनर, वॉटर कूलर तथा फोटोकॉपियर के क्रय हेतु ₹ 33.30 लाख का व्यय संभावित है ।

विशेष न्यायालयों के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 28.80 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 62,10,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

विशेष न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने के लिए ₹ 4.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 4,50,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 1

जिला एवं अधिनस्थ न्यायालयों हेतु न्यायिक भवन निर्माण हेतु ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत जिला एवं अधिनस्थ न्यायालयों हेतु न्यायिक भवनों के निर्माण हेतु ₹ 4500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 55,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4216

मद क्रमांक 2

उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 1500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 15,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 3

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बी टाईप-04, सी टाईप-08, डी टाईप-50, ई टाईप-52, एफ टाईप-43, जी टाईप-230, एच टाईप-450 एवं आई टाईप-400, कुल 1237 आवासीय भवन निर्माण का कुल लागत ₹ 23855.13 लाख अनुमानित है । इस वर्ष ₹ 7000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजना हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 70,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।